क्या शराब माफ़िया से निपट पायेंगे सीपी ?

अवैध रूप से दिल्ली को शराब सप्लाई का धंधा करीब 100 करोड़ मासिक का बताया जाता है। इसमें से 10 करोड़ मासिक पुलिस के हिस्से में आते हैं। इस अवैध सप्लाई का प्रमुख मार्ग थाना सूरजकुंड के इलाके से होकर जाता है। इसका लांचिंग पैड, गांव अनंगपुर है। दिन भर यहां, विभिन्न ठिकानों पर शराब का स्टॉक एकत्र किया जाता है और रात को पचासों लड़के मोटरसाइकिलों पर सप्लाई करने निकलते हैं। इनके अलावा 12-14 केंटर, पिकअप व अन्य वाहन निकलते हैं।

सप्लाई में सुविधा के लिये खड़िया खान नामक एक ठेका भी है। ठेके के नाम पर लोहे का एक बड़ा कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कई गाड़ी माल दिन भर में भर लिया जाता है जिसे रात में पार कर दिया जाता है। यह ठेका कांत एन्क्लेव के भीतर करीब दो-तीन किलोमीटर जाकर एक ऊंचे से टीले पर रखा है। इस ठेके के आसपास करीब तीन-चार किलोमीटर तक कोई आबादी नही है, जाहिर है यह ठेका आम जनता को शराब बेचने के लिये बना ही नहीं है। यह तो बना ही केवल दिल्ली को सप्लाई करने के लिये हैं। इस ठेके तक कोई जाना भी चाहे तो आसानी से जा नहीं सकता, चारों ओर गहरा जंगल है जिसके एक ओर दिल्ली की भाटी माइन्स हैं। दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र में जंगली जीव तेंदुए अजगर पालने के लिये छोड़ रखे हैं। जानकार बताते हैं कि वहां (भाटी माइन्स) से 5 तेंदुए दीवार कूद कर इस ओर आ गये हैं। इसके अलावा कई अजगर भी इधर आ चुके हैं। कुल मिला कर यह इलाका इतना दुर्गम है कि रात तो क्या दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।

इस संवाददाता ने मौका व तमाम चोर रास्तों को देखने के साथ-साथ देखा कि कंटेनर में चल रहे इस ठेके की रखवाली के लिये वहां सदैव तीन-चार सशस्त्र लड़के तैनात रहते हैं। उनकी निगाह बचा कर किसी तरह इस संवाददाता ने, प्रस्तुत फ़ोटो खीची है।

शराब के इस काले धंधे के साथ क्षेत्र के बड़े राजनेताओं व आबकारी विभाग भी जुड़ा है। इस मामले में विभाग का बड़ा मासूम सा तर्क यह होता है कि उन्हें सरकार के राजस्व से मतलब है। यानी सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त होना चाहिये, शराब चाहे जंगल में बिके या शहर में। ऐसा भी नहीं है कि लूट कमाई केवल स्थानीय नेताओं व अफसरों तक ही सीमित रहती हो, इसका बड़ा भाग चंडीगढ़ तक भी पहुंचता है। अब देखना यह है कि नये सीपी साहब इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं ?

नये सीपी का रोड मैप तो बढिया है, इस पर अमल का इन्तजार रहेगा

फ़रीदाबाद (म.मो.) किसी भी नये सीपी की तरह विकास अरोड़ा ने पदभार सम्भालने के अगले दिन (7 सितम्बर) को एक प्रेस वार्ता में बहुत अच्छी-अच्छी घोषणायें की। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इन पर अमल, वे किस हद तक कर पायेंगे ? अब तक का नियम यह रहा है कि किसी भी सड़क हादसे में इस या उस ड्राइवर का चालान कर पुलिस अपने कर्त्तव्य की इतिश्री करती आई है। पुलिस की इसी कार्यशैली को चुनौती देते हुए सेक्टर 16 निवासी मनोज वधवा ने करीब 4 साल पहले हाईकोर्ट में चुनौती याचिका लगाई थी। बाटा मोड़ फ्लाईओवर की बगल से गुजरते हुए राजमार्ग पर पानी से भरे गड्ढे में उनका स्कूटर गिरने से वे, उनकी पत्नी व डेढ-दो साल का बच्चा सड़क पर गिर गये। पीछे से आते एक ट्रक द्वारा कुचले जाने से बच्चे की मौत व पत्नी बुरी तरह से घायल हो गयी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर का चालान करके अपना काम पूरा समझ लिया। लेकिन वधवा ने इसके लिये ट्रक ड्राइवर को नहीं बल्कि सड़क बनाने एवं रख-रखाव करने वालों को दोषी टहराने के लिये हाई कोर्ट में यचिका डाली थी। अन्तिम फैसले का अभी इन्तजार है। अपने घोषित रोड मैप के अनुसार यदि तमाम राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव के बावजूद नई कार्यशैली अपनाते हुये सड़कों से सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी ठहरा कर चालान कर पायेंगे तो इससे सड़क हादसों में कमी आना निश्चित है। इसी के साथ-साथ खुले मैनहोल, सड़कों के किनारे किसी न किसी काम के बहाने खोदे गये गड्ढों को छोड़ देने के लिये भी सम्बन्धित अधिकारियों को लपेटा जाना चाहिये। इसी श्रंखला में सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के लिये भी तो नगर निगम अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही बनती है। यह सब कार्यवाही जेई या एसडीओ तक ही क्यों सीमित रखी जाय, उच्चाधिकारियों को क्यों न बुक किया जाय।

महिला स्कूल कॉलेजों के बाहर निगरानी: काबिले तारीफ़

महिला स्कूल-कॉलेजों व आती-जाती महिलाओं पर आवारा शोदों द्वारा फ़ब्तियां कसने व छेड़छाड़ से निजात दिलाने के नाम पर अक्सर पुलिस जिप्सीइन संस्थानों के बाहर इस तरह खड़ी कर दी जाती है जैसे खेतों में पशु-पक्षियों को डराने के लिये बिजूके। समझने की बात है कि पुलिस वाहन के आस-पास भला कोई लफंटर छेड़छाड़ क्यों करने लगा, वे कहीं दूर, पुलिस की निगाह से बच कर अपनी गंदी हरकतें करते रहते हैं और पुलिस वाहन में बैठे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पीट कर निकल लेते हैं। जाहिर है, इस समस्या का सही हल यही है जो सीपी ने सिविल ड्रेस में छापामारी की योजना बनाई है।

ट्रैफ़िक व्यवस्था में सुधार

शहर के बीच से गुजरने वाले राजमार्ग सहित तमाम सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि उन पर ट्रैफ़िक जाम की कोई समस्या नहीं आ सकती, बशर्ते कि सड़कों को केवल चलने के लिये ही रखा जाय। समस्या केवल सड़कों पर अवैध पार्किंग एवं कब्ज़ों के कारण ही पैदा होती है। शहर की भीतरी सड़कों के अलावा राजमार्ग के किनारे ट्रकों की लम्बी लाइन आराम से खड़ी रहती है। बाटा फ्लाईओवर से उतर कर हार्डवेयर चौक तक की सड़क पर दोनों ओर ट्रकों व बड़े ट्रालों का जमावड़ा लगा रहता है, रही-सही कसर मिट्टी के बर्तन व अन्य सामान बेचने वालों ने पूरी कर छोड़ी है। सेक्टर 14 से सेक्टर 9 को जाने वाली सड़क पर सदैव ही सामान से लदे वाहन कम्पनी के भीतर जाने की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि सामान्य यातायात अक्सर जाम हो जाता है। राजमार्ग के हर चौराहे पर सर्विस लेन पर अवैध कब्जे यातायात में रूकावट डालते हैं।

नशे और अवैध हथियारों के तमाम व्यापारी पुलिस के सम्पर्क में

ये दोनों व्यापार कहने को तो चोरी छिपे चल रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई पुलिस की नज़र से छिपा हो और पुलिस को अपनी कमाई में से हिस्सा न देता हो। ये धंधेबाज पुलिस को पैसा देने के साथ-साथ खानापूर्ति के लिये समय-समय पर कुछ माल के साथ अपना कोई कारिंदा भी देते हैं। पुलिस इन पर कार्यवाही करके अपनी पीठ थपथपाते हुए आंकड़ेबाज़ी का खेल खेलती रहती है। यदि ईमानदारी से पुलिस चाहे तो ये कारोबार एक दिन भी नहीं चल सकते। इसके लिये सीपी को खाकी में छिपी उन काली भेड़ों की बलि चढानी होगी जो इन धंधों से जुड़े हैं। वरना यह सारा धंधा ज्यों का त्यों चलता रहेगा।

परिवहन मंत्री मूलचंद का विभाग फ़िर से पुलिस के पहरे में

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

परिवहन विभाग के प्रधान सचिव पद पर तैनात शत्रुजीत कपूर के पदोन्नत होकर डीजीपी विजिलेंस लग जाने के बाद विभाग के मंत्री एवं बल्लबगढ से विधायक मूलचंद शर्मा को शायद एक बार यह उम्मीद बंधी हो कि अब उनका विभाग पुलिस के शिकंजे से मुक्त हो पायेगा और उनकी अपने विभाग में थोड़ी-बहुत चल पिल सकेगी। लेकिन बीते सप्ताह खट्टर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फ़ेरते हुए इस पद पर एडीजीपी कला रामचंद्रन को नियुक्त कर दिया। कला रामचंद्रन 1996 बैच की आईपीएस अधिकारी है; वे बीते कई वर्षों से भारत सरकार के आईबी में अपनी सेवायें दे रही थी उनकी तैनाती चंडीगढ में ही थी।

केन्द्र से वापस आने के बाद हरियाणा सरकार उनकी ईमानदारी, काबिलियत एवं इंटिग्रिटी को देखते हुए कोई अच्छी पोस्टिंग देना चाहती थी। भरोसेमंद सूत्रों की यदि मानें तो उन्होंने फ़रीदाबाद व गुड़गांव का सीपी बनना इस लिये स्वीकार नहीं किया कि वे स्थानीय राजनेताओं के साथ ताल-मेल नहीं बैठा पायेंगी। इसी चक्कर में वे कुछ माह बिना किसी तैनाती के रहीं। अब महकमाना रद्दोबदल होने के चलते उनके लायक एक बेहतरीन पोस्ट सरकार को नज़र आई तो उन्हें यह नियुक्ति मिली।

शासक वर्ग के भीतर लूट-कमाई के बंटवारे की सटीक जानकारी रखने वालों का मानना है कि रामबिलास शर्मा के चुनाव हार जाने के चलते ब्राह्मण कोटे का मंत्री पद तो मूलचंद को मिल गया लेकिन खट्टर सबसे अधिक लूट-कमाई का परिवहन विभाग मूलचंद को नहीं देना चाहते थे। राजनीतिक दबाव व घेराबंदियों के चलते, मजबूरन खट्टर को न केवल परिवहन बल्कि माइनिंग विभाग भी मूलचंद को देने पड़े। विभाग तो दे दिये लेकिन मूलचंद के मुंह पर छीकी लगाने का काम करते हुए सर्वप्रथम आईजी अमिताभ ढिल्लों के नेतृत्व में एक अच्छी-खासी टीम खड़ी कर दी जिसका काम अवैध माइनिंग व ट्रकों यानी डम्परों की ओवरलोडिंग तथा अवैध माल ढोने को सख्ती से रोकना था। बीते वर्ष पाठकों ने नोट किया होगा कि किस तरह आये दिन पुलिस की ये स्पेशल टीमें अवैध माल ढोने वाले डम्परों से टकरम-टकरा हो रही थी। इसी दौरान मंत्री महोदय खुद भी सड़कों पर छापेमारी का नाटक करके यह दिखाते रहे कि वे भी मंत्री हैं और यह सारा अभियान उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है।

खट्टर द्वारा किया गया उपाय काफ़ी नहीं था। राज्य भर में फैले हुए आरटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे होने के साथ-साथ मंत्री महोदर की सेवा-पानी भी ठीक-ठाक कर रहे थे। इसके अलावा परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का थोक व्यापार चंडीगढ स्थित इसके मुख्यालय से चलता था। इन सब धंधों पर नकेल कसने के लिये खट्टर ने अमिताभ ढिल्लों को विभाग का आयुक्त तथा शत्रुजीत कपूर को प्रधान सचिव तैनात किया था। कपूर की कार्यकुशलता एवं ऊपरी स्तर पर सिस्टम को चुस्त-दुरूस्त करने में उनकी योग्यता के कायल तो खट्टर पहले से ही थे। इन दो शीर्ष नियुक्तियों के अतिरिक्त राज्य भर में तैनात आरटीओ पदों पर भी डीएसपी नियुक्त कर दिये गये। इस से पहले यह चार्ज ज़िलों के एडीसी (अतिरिक्त उपायुक्तों) को भी देकर देखा गया था। लेकिन खट्टर सरकार को इससे संतुष्टि नहीं हुई तो ये तमाम पद भी पुलिस को ही सौंप दिये गये।

खट्टर की इस रणनीति से मंत्री महोदय के मुंह पर लगी छीकी कितनी कामयाब हो पाई यह तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु निचले स्तर यानी ज़िला स्तर पर विभागीय भ्रष्टाचार में कोई कमी आई नहीं लगती। हां, अन्य राज्यों को जाने वाली एनओसी, परमिट फ़ीस के ड्राफ्ट आदि में जो गबन आदि हो जाया करते थे, वे जरूर कम्प्यूटर व ऑनलाइन सिस्टम के चलते काबू में आ सके हैं। इसके अलावा उच्च स्तर पर होने वाली भारी-भरकम खरीद से मिलने वाले कमीशन की मॉनिटरिंग भी कुछ नियंत्रण में आ गयी होगी।

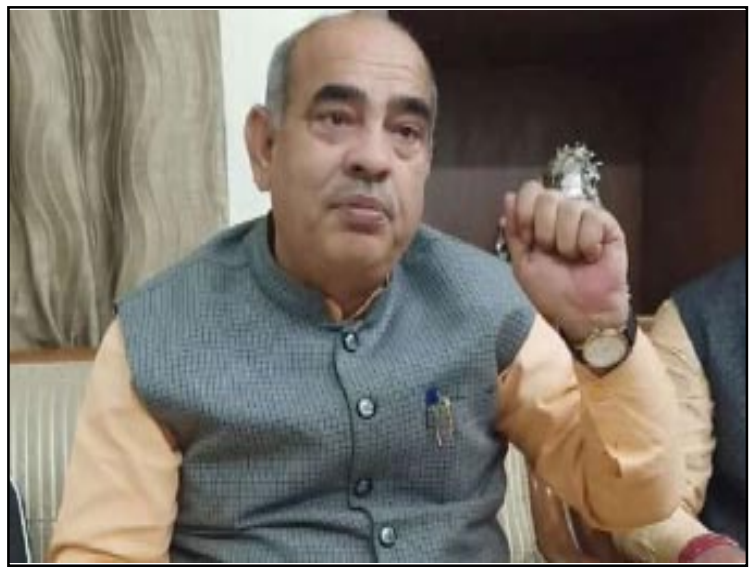

लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह सब करने के लायक कोई आईएएस अफ़सर खट्टर के पास नहीं हैं ? क्या हरियाणा में तैनात सभी आईएएस एकदम नाकारा व बेइमान हैं ? यदि ऐसा है तो सरकार ने उन्हें क्यों पाल रखा है ? सर्व विदित है कि कोई भी अफ़सर डकैतियां केवल तब ही मारता है जब उसके ऊपर बैठे राजनेता का आशीर्वाद एवं संरक्षण उसे प्राप्त हो। इसके चलते पूरे राज्य में ही भ्रष्टाचार का खुला तांडव हो रहा हो तो एक परिवहन विभाग या उसके 'गरीब' मंत्री के मुंह पर छीकी लगाने का क्या मतलब ? आखिर उसने भी करोड़ों खर्च करके चुनाव जीता है, अगले चुनाव में फ़िर खर्च करना है, यह सब आखिर कहां से आयेगा, मात्र मिठाई बेचने से तो आने से रहा।

दूसरा अहम सवाल यह भी है कि उक्त तीनों पुलिस अधिकारी जब इतने ही बढिया हैं तो क्या पुलिस महकमे में इनके करने लायक कुछ नहीं ? क्या पुलिस महकमे को इन अफ़सरों ने इतना पाक-साफ़ बना दिया कि अब इनकी वहां जरूरत नहीं, अब इनसे अन्य विभागों का शुद्धिकरण कराया जायेगा ?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06